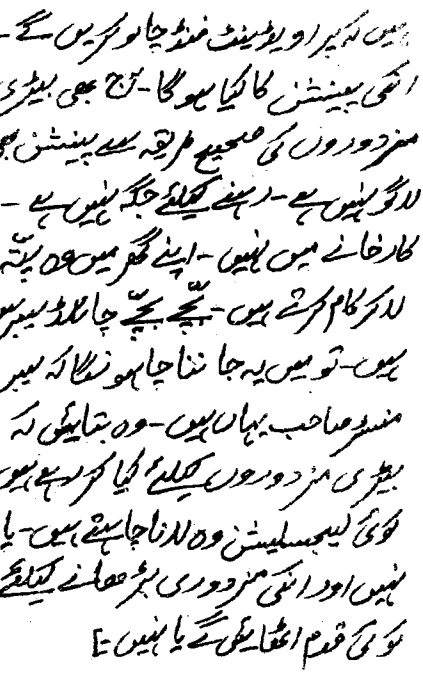

SHRI RAHMAN KHAN (Karnataka): Madam, I associate myself with the points raised by Shri Balanandan.

मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश) : मैडम्, मेरा एक सुझाव है। वह प्रश्न की शकल में भी है। उत्तर प्रदेश में 1993 में मुलायम सिंह सरकार 35 रुपया हजार बीड़ी की मजदूरी का शासनादेश हुआ और वह फिर कानून भी बना विधान सभा में। मै क्योंकि लेबर मिनिस्टर भी रहा था इसलिए मेरी बीड़ी मजदूरों से ज्यादा दिलचस्पी रही। मेरे शहर में बहुत ज्यादा बीड़ी का काम होता है। इसका इतना लम्बा प्रोसस है मैडम्, कि रात में बीड़ी का पत्ता भिगोया जाएगा, सुबह तक वह फूलेगा और पूरा परिवार उसमें लग जाता है बीड़ी के पत्ते को काटने में और बनाने में। असल समस्या यह है कि जो शासनादेश है या जो कानून है किसी भी प्रदेश का, जहां मिनिमम वेजेज लागू है, मसलन उत्तर प्रदेश है, वहां 35 रुपए हजार की बीड़ी की मजदूरी का कानून बना हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं जहां 35 रुपया हजार बीड़ी की उज़रत मिलती हो। यहां प्रश्न सिर्फ एक है। सरकार अगर इसको सुनिश्चित करदे कि अमरोहा जहां नम्बर एक पर सबसे ज्यादा बीड़ी बनती है, रामपुर जहां नम्बर दो पर बनती है, गुरसहाय गंज, इलाहाबाद इस तरह बहुत जिले हैं जहां बीड़ी बहुत ज्यादा बनती है। अगर सरकार सिर्फ इतना एश्योरेंस दे दे, इतना सुनिश्चित करदे कि जो बीड़ी की मजदूरी की दरें सरकार की तरफ से घोषित हैं वह लागू की जाएंगी। ऐसा होता है बीड़ी मालिकान सांठगांठ कर लेते हैं मजदूरों से। उनके बीच में एक और एजेंसी होती है जो बीड़ी बनवाती है और कम दामों पर बीड़ी बनकर मालिक के पास आ जाती है। अगर कोई ऐसा कानून बन जाए। मसलन बीड़ी का कोई मालिक बीड़ी बनवाता है और पुरी दरें नहीं देता है और उस पर छापा मार दिया जाए तो सिर्फ 50 रुपए का जुर्माना पड़ता है। इससे ज्यादा नहीं है। ऐसा कानून हम बनाने की सोच रहे थे, जिसमें नॉन-बेलेबल आफेंस हो, हथकड़ी डले और मालिक जेल जाए। अगर यह डर पैदा कर दिया जाएगा कि जो मालिक बीड़ी की न्यूनतम दरें नहीं देगा उसके हाथों में हथकड़ी पड़ सकती है। मिनिमम वेजेज जिन प्रदेशों में हैं, मसलन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिनिमम वेज है 35 रुपया प्रति हजार। पूरे प्रदेश में इसको सुनिश्चित कर दिया जाए कि यह मजदूरी हर मजदूर को पूरे प्रदेश में मिलेगी तो इस समस्या का बहुत हद तक समाधान संभव है।

The Vice-Chairman (Shri MD. Salim) in the chair

RE: AMERICAN VICE-PRESIDENTS LETTER TO DR. AULAKH MAKING REFERENCE ABOUT KHALISTAN.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA (Punjab): Sir, I would like to draw your kind attention to a very sensitive issue. The Vice-President of America, Mr. Al Gore, wrote a letter to a non-existent, unknown and letterhead body called the Council of Khalistan. He wrote this letter to the President of the Council of Khalistan, Dr. Gurmit Singh Aulakh. It is strange that America's second most powerful

man acknowledges a letter from such a body. The most shameful thing is that he accepts a non-existent geographical identity like Khalistan. One really wonders what kind of a ruler is there in America. Mr. Vice-Chairman, Sir, before I go into the intention an other dimensions of the issue, at the outset, I would like to know whether the Government of India has taken up this issue. The issue in general is that the American administration is following such cases and furthering the agenda of Khalistan. Actually I don't wish to raise this kind of an issue. But I am perturbed because in that letter Dr. Gurmit Singh Aulakh has mentiond that there is an ongoing conflict in the State of Punjab. We know, the whole world knows, that many American legislators came here and they themselves saw that there was nothing of that kind. Punjab is abnormally normal. From 1993 onwards, Punjab has been the most peaceful State in the country. That is why I said Punjab was abnormally normal today. People like Mr. Gore, Vice-President of America, by raising such a voice, are giving a powrful weapon to disgruntled people. I really want to know what the aim is. Is it that some innocuous administrator submitted a lette to him and he signed it? Or, is it a politically stupid letter that he wrote? Is it a classic case of American diplomacy? I do not know. But I would like to know: Is is some kind of an American classic diplomacy first to give powerful and special attention to such casuss that can distabilise a democracy and later on withdraw it? This has been their practice. First they build up a movement and later on they deny it. Is it a game really? What happens in the process? Mr. Vice-Chairman, Sir, you know that thousansd of people have gone to America, UK and other places and have sought political asylum there. I am told that nearly 10,000 people sought political asylum on the ground of oppression in the State of Punjab when there was absolutely no oppression in Punjab. When such stories prevail, there are no American media and American judiciary to take congnisance of the fact that there is total peace in Punjab. If the Vice-President of America speaks this kind of a language, the American judiciary takes a similar view. What happens in the process? There are stories all over the world that there is oppression in Punjab because 10,000 people sought asylum in America. Those who are going on a political asylum route, are looking only for an immigration visa and nothing else. They make stories. My point is, the American administration should not encouage such thing which only help the disgruntled elements to keep such separatist movement going on and on. This is the most dangerous thing. The American adminsitration should perform a responsible role. Wherever there are such things they should take some other measures, to curb such things so that Dr. Gurmit Aulakh kind of people do not raise such issues and make money for themselves. When he helps people to get political asylum really there, then what happens is, a lot of money is collected by Dr. Aulakh and such kind of people. It should be discouraged. My second point, Mr. Vice-Chairman, to you is, that the Indian Government must take up the matter. I am deliberately saying that the American Vice-President is involved. Let him deny. Let the Indian Government pursue this with the American administration; let the American Vice-President deny that he has said it. If he has not denied, then it is a serious matter. Now the point I am making is that, if the American administration refuses to budge then there are bad intentions behind this. I am saying this for a known reason. As I have said earlier, it could be a clandestine way of destabilising democracies in Asia and Africa. So, I would like to know from the Government of India whether this matter has already been taken up by the Indian Government with the U.S. Government and if not, whether they are going to take up this matter seriously so that a proper explanation is called for. Secondly, the Indian Government must take such issues more seriously and tell the American adminsitration not to entertain and ackowledge such letters from letter-head organisations. Thank you very much.

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदय, अमेरिका के उपराष्ट्रपति अलगौर ने खालिस्तान के विषय में जो पत्र लिखा है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं

और कठोर निन्दा करता हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, जो डॉक्टर औलक ने उनको चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा था:

since the USA "supports freedom and democracy" the world over, the Clinton administration should support the "Sikhs in their freedom struggle to liberate Khalistan from India."

यह औलक उसको लिखता है और उसके जवाब में जो गोर ने चिट्ठी लिखी उसमें लिखा है:

"Thank you for writing to me regarding the ongoing civil conflict in Khalistan. I appreciate hearing your views on this serious subject."

उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां पर अभी पंजाब में चुनाव हुए। पंजाब के चुनावों में खालिस्तान के समर्थक लोगों को जानते जब हंई, उनको कोई वोट नहीं मिला। पंजाब की जनता ने सिद्ध किया है कि न खालिस्तान का कोई अस्तित्व है और न ही खालिस्तान का कोई समर्थक हिन्दुस्तान में है। खालिस्तान जैसी कोई चीज़ नहीं है। परन्तु अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने इस तरह की चीज़ को लिखा और न केवल लिखा बल्कि उसको एप्रिशिएट किया और उससे कहा कि उसमें हम आपकी मदद करेंगे। आगे वह लिखते हैं :

"Your views are very importat to us as the President and I," i.e. the Vice-President "formulate policies to advance the cause of peace around the world."

और इसलिए उसको लिख रहे हैं कि यह बहुत अच्छा काम आपने किया है और आपने हमें लिखा है। हम इस प्रकार की नीतियां बनाएंगे जिससे शान्ति हो। महोदय, यह शान्ति नहीं, यह तो अशांति पैदा करने वाली चीज़ है अमेरिका के राष्ट्रपति किलंगटन की एडमिनिस्ट्रेशन लगातार भारत विरोधी वक्तव्य देते रहे हैं। किलंगटन जब यूएनओ के अंदर स्पीच दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कश्मीर के बारे में वक्तव्य दिया। वह भारत विरोधी वक्तव्य था। जैसे कश्मीर कोई सैपरेट स्टेट हो, डिस्टर्ब्ड स्टेट हो इस तरह की बात कही। रैफल के वक्तव्य लगातार आते रहे इसलिए आते हैं कि भारत सरकार ने कभी बहुत जोर से या कठोरता से अमेरिका को यह नहीं बताया कि यह जो शत्रुतापूर्ण आपके स्टेटमैंट्स हैं, इनको रोका जाए, इन पर लगाम लगाई जाए और भारत के बारे में इस तरह के वकतव्य देने के लिए उनको रोका नहीं गया। अगर भारत इस तरह के सॉफ्ट ऑपशंस नहीं लेता तो शायद इसको बार-बार रिपीट करने की बात नहीं होती। जबकि हिन्दुस्तान में एक आदमी उसका समर्थक नहीं है, उस समय अमेरिका में खालिस्तान को जिन्दा रखना, मैं समझता हूं कि इसको हमें भारत विरोधी कार्यवाही के तौर पर लेना चाहिए। इसलिए मैं आपसे और भारत सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि भारत कठोर विरोध प्रकट करे। न केवल कठोर विरोध प्रकट करे बल्कि इसको हाईएस्ट लेवल पर उनके साथ इस सवाल को उठाये। दूसरा यह है कि अभी तक भारत सरकार की पब्लिसिटी इतनी वीक है कि वहां पर जो भारत विरोधी सीनेटर्स हैं, उनके पास पूरे फैक्ट्स नहीं पहुंचाये जाते है। उनके पास पूरे तथ्य नहीं पहुंचाये जाते हैं। वहां पर जो हमारा प्रचार होना चाहिए वह इतना हल्का है कि पाकिस्तान के प्रचार के मुकाबले में हम टिक नहीं पा रहे है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आक्रामक पब्लिसिटी करनी चाहिए, फैक्ट्स लोगों के सामने रखने चाहिए पंजाब और कश्मीर के बारे में। जो हमारे भारतीय एनआरआई हैं वहां पर उनकी भी हमने कोई मदद नहीं ली है। अमरीका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग बहुत प्रभावी हैं, वे वहां के सीनेटर्स और कांग्रेसमैन के ऊपर भी प्रभाव डाल सकते है। इसलिए भारत सरकार इस मामले में साफ्ट पालिसी एडाप्ट न करे और साफ तौर पर अमरीका को बताये कि ज्यादा देर तक इस प्रकार के शत्रुतापूर्ण बयानों को भारत सहन नहीं करेगा और इसके बारे में हमें अपनी नीति उसी के मुताबिक बनानी पड़ेगी।

SHRI K.R. MALKANI (Delhi): Sir, we want to associate ....(*Interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Now, Shri Gurudas Das Gupta.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Utter Pradesh): Sir, may I be permitted to associate ....(*Interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Let Mr. Gurudas Das Gupta speak first. You may associate yourselves after he concludes.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, I feel that the implication of such a statement, such a communication is much more than what we have been able to understand. It is not a question whether a letter-head organisation is being recognised by the UST. Nor is it a question tha the Khalistani supporters have lost the recent election battle in Punjab. This is not the significance. Significance has to be attached to the use of the term 'peace' by that gentleman. If he is referring to peace, it means that there is a war going on in Punjab. The implication is that the forces of secession that had been at work in India, in many parts of the country, are being encouraged. The forces of secession, the forces of division, the forces which are acting against India's integrity are being encouraged by the Vice-President of the United States of America, which means, by the American Administration and which means the so-called first global power of the world. This is an attempt to balkanise India, to divided India, to weaken India. This is a policy which they have been pursuing for long. We have seen them in Kashmir. We have seen them in Punjab. And we have every reason to believe that there is a foreign hand in other parts of India also. Therefore, the only intention behind such a unprecedented, unheard of, undiplomatic and unfriendly statement is to see that India is balkanised, India is divided and India is weakened. Therefore, it is a question of Indian patriotism and national integrity being attacked. We condemn the statement. Secondly, we want the Government of India to condemn this. It is not a question of soft-pedalling. India's national integrity cannot be bartered, whoever may be in the Government. This Indian Parliament condemns this statement. We call upon the Govenrment of India to condemn this statement. Another important question is, at a time when normalcy is returning to Punjab, it is an attempt to bring back the forces of violence in Punjab. It is not a question of who won the elections or who lost the elections in Punjab. It is something more than that. It is being done deliberately to give a semblance of respect-ability to the Khalistan movement so that it can again unleash the region of terror and violence on the peace-loving people of Punjab. My third point is, I apprehend....*(Interruptions)*....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Fourth point.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, my fourth point is, I apprehend that there is a collusion between the circles of power in America and the forces of secession and violence in India because we know that arms-training camps were set up in some parts of the world other than India and Pakistan. I am mentioning once again that training centres were set up in some parts of the world other than Pakistan. Who are their patrons? It is the Americans who may have been trying to pull the strings and who may have been their patrons.

Lastly, at a time when India has decided to open a dialogue with Pakistan for peaceful solution of the problems and for restoration of friendship with Pakistan, Bangladesh and other neighbours, this is an attempt to really put our efforts in danger. India's initiative for peaceful relations with its neighbours is sought to be jeopardised by the American ruling circles. I condemn this. The Government should also condemn unequivocally this move of the American administration.

SHRI N.K.P. SALVE (Maharashtra): Sir, I associate myself with what has been expressed by the earlier speakers. The Vice-President of the United States of America is an important man and a knowledgeable man. But it is obvious, in the light of what he has written,

that he has no sense of history and no sense of geography. Obviously, he has no sense of current affairs. But the matter is serious and if it is motivated by some sinister considerations, then we need to take it far more seriously than what it appears to be on the face of it. But, in the meanwhile, I suggest, through you, that the External Affairs Minister should immediately summon up the American Ambassador and ask of him what was it that went behind this kind of a letter. Where is Khalistan? Does it exist only in the figment of his imagination or is there really something sinister behind this? There could be. But I would not go as far as Gurudas Das Gupta has gone, to impute motives straightway. But we should find out. There are people in high offices who are utterly ignorant of things. He may be one of them. But I don't what to give him the benefit of doubt unless we summon...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, you are giving the benefit of doubt to the Americans after this statement!

SHRI N.K.P. SALVE: What I am saying is, I am not condoning that for a moment. His patriotism is certainly not less than mine. He can have different perceptions.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh): He is giving the benefit of doubt on the basis of his knowledge, whether that man knows about India. That is what he said.

SHRI N.K.P. SALVE: I am saying he is unaware of history, geography and current affairs.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Too innocent an expression, Sir!

SHRI N.K.P. SALVE: But this is far too serious a matter to be left overlooked. Therefore, call for the Ambassador post-haste and ask of him what nonsense is this that the Vice-President is talking about. And if he apologises to us, then it may have an entirely different colour.

SHRI E. BALANANDAN (Kerala): Sir, that is a very serious matter that has been raised by Shri Surinder Kumar Singla. All the hon. Members have condemned the Vice-President for writing such a letter. Sir, they take India for granted. The American rulers take India for granted. They think that they can easily do anything against our country. They are talking about Khalistan because we have been able to restore peace in Punjab. Now the American administration is again worried about it. They are writing letters to somebody to again rake up the Khalistan question. Therefore, the Government of India should take immediate steps to convey to them that this kind of interference will not be tolerated by India. As a Government, we must rise to the occasion and demand the withdrawal of this letter that has been written by the Vice-President of USA.

श्री एस.एस. अहलुवालिया (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला ने जो सवाल उठाया है कि अमरीका के उपराष्ट्रपति ने श्री गुरमीत सिंह ऑलख को चिट्ठी लिखी है, यह दुर्भाग्यपूर्ण चिट्ठी है। आप के अखबार पॉयनीर में लिखा है 'Send Gore back to school'. जो लोगों के बारे में, हिन्दुस्तान के बारे में, हिन्दुस्तान की टॉपोग्राफी के बारे में, हिन्दुस्तान की क्लचर के बारे में, सोशल हिस्टरी के बारे में और यहां के करन्ट अफेयर्स के बारे में न जानते हों और इसके बावजूद भी ऐसा बिहेवियर करते हों तो मैं समझता हूं कि सदन के सभी पक्ष के लोगों ने भर्त्सना की है जो उचित ही है। यदि यहां हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारी कूटनीति में कहीं न कहीं कमजोरी है। हमारे राजदूतों का काम है कि वे यह भी देखें कि किस तरह से लोगों को एज्युकेट करें, लोगों को बतायें, किस तरह फीड बैक दें। वहां भी [illegible]

हम सिर्फ गुरमीत सिंह ओलक को ही दोष दें तो नहीं चल सकता है कि वे ऐसा पत्राचार क्यों कर रहे हैं। महोदय, हम सबको मालूम है कि खालिस्तानी डालर छपे, पासपोर्ट छपे तो वह अमृतसर में नहीं छपे, वे छपे अमेरिका में। जब उन्होंने मैप बनाया, एटलस बनायी और दिखाया कि हिन्दुस्तान का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में है और कौन सा हिस्सा खालिस्तान में है तो उस वक्त भी ये सारे मैप वहीं छापे गए थे। तो कहीं न कहीं किसी न किसी ताकत से उनको मदद मिलती रही है। यहां पूरा सिख समाज चाहे वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक हो उनसे इस मूव का विरोध किया है। लेकिन इसके बावजूद कभी-कभी दुर्भाग्य यह होता है कि उस चीज को हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। यह आवाज क्यों उठती है? यह इसलिए कि उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है। जब उनको न्याय नहीं मिलता है तो ऐसी आवाजें उठती हैं। शायद ओलक के साथ कोई भी आदमी खड़ा नहीं होता अगर 84 के दंगों के अपराधियों को सजा मिल गई होती। अगर न्याय पूरी तरह से हो गया होता तो ऐसा न होता। अगर न्याय और अन्याय को एक तराजू पर नहीं तोला गया होता और न्याय का दर्जा ऊपर होता तो शायद ऐसे सपोर्टर उन्हें नहीं मिलते। मैं कहूंगा कि इन सब चीजों पर कंट्रोल करने के लिए-हमारे घर की जो लड़ाई है वह लड़ाई हम घर में लड़े लेंगे पर दुश्मन को कभी भी हम भारत माता का खंडन करने के लिए अलाऊ नहीं करेंगे इसलिए हमें आज फैसला लेना चाहिए और सदन में यूनैनीमसली रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि हम इस कृत्य को कंडैम करते हैं और आप गवर्नमैंट को डाइरैक्टिव दें कि गवर्नमैंट अमेरिकन अम्बेसडर को एक्सटर्नल एफियर्स मिनिस्ट्री में बुलायें और उसको डांट पिलाकर सावधान करें कि आइंदा भारत माता के टुकड़े करने वालों को अगर उन्होंने सराहा या उनको मदद देने की कोशिश की तो यह हमारे बर्दाश्त के बाहर की चीज होगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): मैं समझता हूं कि यह एक गंभीर मुद्दा है। सिंगला साहब ने जो यह मुद्दा उठाया है इससे सारा हाउस, हाउस के सारे सदस्य सहमत हैं।...(व्यवधान)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: The Government should react to it...(*Interruptions*)...The Government should react to it.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): ...A after which we should adopt a resolution...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): The Minister will communicate to the Minister of External Affairs the displeasure and sentiments of Rajya Sabha as a whole. ...(*Interruptions*)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Some statement should come from the Government as to what action it is going to take.

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): अमेरिकी राजदूत द्वारा यह बात ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): सारा हाउस सहमत है। भाषण करने की जरूरत क्या है। सिंगला जी ने जो बात यहां पर उठाई है उससे सारा सदन सहमत है। ...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: रामूवालिया जी आप कल भाषण देकर आए हैं। खड़े होकर बोलिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Let the Minister say something. ...(*Interruptions*)...

SHRI R.K. KUMAR (Tamil Nadu): Sir, I condemn it. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, we want a statement from the Government. ...(*Interruptions*)...

SHRI NARENDRA MOHAN: Sir, the American Ambassador is propagating two-nation and three-pation theory in India.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Please hear the Minister.

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): सर, सदन के सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से, युनेनीमसली अमेरिकन वाइस प्रेसीडैंट के उस खत का, जो उन्होंने एक नाम निहाद, सिंगला जी ने ठीक कहा, जो कागजी आर्गनाइजेशन है, उसके उत्तर में लिखा है, उसका जो कंडेमनेशन हुआ है, उसमें भारत सरकार हाउस के जजबातों के साथ है। मैं व्यक्तिगत तौर पर एक लफ्ज कहकर फिर सरकार की तरफ से कहूंगा। मैं खुद सबसे ज्यादा, सरदार अहुवालिया जी जानते हैं कि मैं खुद खालिस्तान के खिलाफ प्रैक्टिकली लड़ा हूं और अमेरिका, कनाडा में जाकर मैंने झंडा उठाकर कहा था कि ओ खालिस्तानियों तुम डालर के खालिस्तानी हो, डालर खाने के खालिस्तानी हो। भारत की एकता के लिए एक-एक सिख अपने खून का आखिरी कतरा बहा देगा। कोई इसको रोक नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से इस बयान पर नापसंदीदगी का इज़हार करते हुए अपने कलीग श्री

यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी से कभी चावल से कभी चावल के दाने जितना भी पीछे नहीं हटेगी।...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: राई के दाने जितना।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: राई के दाने जितना भी पीछे नहीं हटेगी।...(व्यवधान)...

श्री परेन्द्र मोहन: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अमरीका के राजदूत तक यह पहुंचा देंगे। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप बैठ जाइये ...(व्यवधान)... आप इस तरह से नहीं पूछ सकते।

श्री संजय निरुपम: उपसभाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): इतने स्पेशल मैंशन है, वह होने हैं।...(व्यवधान)...वह विषय खत्म हो गया है, बैठ जाइये...(व्यवधान)...

I am not allowing you.

सदन के भी कुछ नियम हैं।...(व्यवधान)...

SHRI SANJAY NIRUPAM: *

SPECIAL MENTIONS

Need to control price rise of essential commodities and to protect the interest of labour class and other weaker sections of the society

श्री इकबाल सिंह (पंजाब): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी माध्यम से देश भर में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार ने उचित दर की दुकानों पर बिकने वाली राशन की चीनी की कीमत बढ़ा दी है ...(व्यवधान)...

श्रीमती रेणुका चौधरी (आंध्र प्रदेश): ज़रा जोर से बोलिये आवाज बहुत कमज़ोर है ...(व्यवधान)...

श्री इकबाल सिंह: आपका ध्यान रामूवालिया जी की बातों की तरफ है (व्यवधान) आप मेरी तरफ ध्यान दीजिये (व्यवधान) एक रूपया पैंतालीस पैसे प्रति किलो राशन की चीनी की कीमत बजट से पहले बढ़ा दी गई है। राशन की चीनी की दर में इतनी वृद्धि कर देने से खुले बाजार में चीनी की कीमत बढ़ जाएगी। इससे पूर्व सरकार बजट से पहले गैस, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में वृद्धि कर चुकी है। इसका असर बाज़ार में उपलब्ध वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ा है। यहां तक कि आटा, नमक, चाय, चावल आदि के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है। इस मूल्य वृद्धि से गरीब और श्रमिक वर्ग बहुत ही प्रभावित हुआ है। उसके पास पहले से ही परचेज़िंग पावर नहीं है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कर देने से उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है परचेज़िंग पावर के अभाव में वह अपने बच्चों का पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा किस हद तक पूरी कर पाएंगे, इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। देश में जिस तरह से मंहगाई बढ़ रही है, उससे यह लगता है कि यदि सरकार ने इस मंहगाई को रोकने के लिए ठोस एवं प्रभावी उपाय नहीं किये तो इसका असर गरीब वर्ग पर पड़ेगा और मंहगाई का प्रवाह इतना तेज़ हो जाएगा कि उसे रोक पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। बजट से पहले एस.टी.डी. कालज़ के रेटों में भी वृद्धि कर दी गई। रेल मंत्री जी ने अभी-अभी रेल यात्री किराये तथा माल भाड़े में वृद्धि कर दी है। हमारे देश में 35 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें राहत अवश्य मिलनी चाहिये। देश में जिस कदर मंहगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के उपाय करें। देश में गरीब वर्ग को मिलनी वाली सब्सिडी जारी रखनी चाहिये क्योंकि हमारा देश कल्याणकारी समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। अगर देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि रोकने में सरकार सफल नहीं होती तो उसे मजदूरी की मजदूरी में वृद्धि करनी होगी। राशन व्यवस्था समाप्त करके बाज़ार में सभी चीज़ों को खुला छोड़ दिया जाए तो काफी हद तक समस्या हल हो सकती है।

सर, मैं तो एक जानकारी देना चाहता हूं। हाल ही में मैंने 13.2.97 के हिन्दुस्तान टाइम्स में पढ़ा कि उड़ीसा राज्य के बोलांगीर जिले में इतनी भीषण गरीबी है कि वहां के गरीब पालन-पोषण के लिए अपने छोटे-छोटे मासूम बच्चों को बेच रहे हैं, उनको गिरवी रख रहे हैं क्योंकि उस जिले में गरीब लोगों के लिए कोई कदम नहीं है। वहां लोग भुखमरी से मर रहे हैं। गरीब लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है।

सर, एक ऐसी ही घटना और मैंने समाचार-पत्र में पढ़ी कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में डाबड़ी थाना क्षेत्र में बस्ती विजय एंक्लेव में आर्थिक संकट और भुखमरी से तंग आकर एक तिपहिया चालक ने अपनी पत्नी और तीन मासूम बच्चों की हत्या कर दी। देश के अन्य आदिवासी

*Not recorded.